

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 13/22

वर्ष 2022

जीसीएमएस संख्या 2022/84

बउनवानी:—राजेश शर्मा पुत्र श्री देवी नारायण शर्मा निवासी खण्डार, उ.मू. दुकानदार ग्राम पंचायत
खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक
5.8.2020 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
आर्डर 1976)

उपस्थित:—श्री मुकेश तेहरिया
श्री मुनेष मीना (प्रवर्तन निरीक्षक)

वकील अपीलान्त
पैरोकार रसद

—:निर्णय :-

दिनांक:— 12.10.2022

प्रस्तुत अपील अपीलान्त द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक
5.8.2020 जिसके द्वारा अपीलान्त का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरुद्ध इस कथन के साथ
प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है, जिसको खारिज
फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पों. की तलवी
जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर बहस
वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश
जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के
कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार
का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 7/2011 है तथा प्रार्थी वर्ष 2011 से बिना
उपभोक्ताओं की शिकायते के ईमानदारी से राशन सामग्री का वितरण करता रहा है। यह तर्क भी दिया
कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016, 5.8.2016 को पोस मशीन
द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये तत्पश्चात जिसके अनुसार
उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के
रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. नम्बर आने पर ही उपभोक्ता को राशन सामग्री का वितरण
किया जाता है। इसलिए कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं रहती है ओर ना ही राशन कार्ड मे
वितरित की गयी राशन सामग्री की एन्ट्री करने की आवश्यकता रहती है। अपीलान्त द्वारा राशन
सामग्री का गबन नहीं किया है बल्कि उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण पूर्व में जिला रसद
अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.3.2015 द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान की
आपूर्ति एवं वितरण कार्य पर रोक लगा दी गयी है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक
6.4.2015 से चालू की गयी है। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा अपने आदेश दिनांक
29.6.2016 द्वारा पुनः प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया जिसको
प्रार्थी द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती दी जाने पर मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक
7.9.2016 द्वारा अन्तरित स्थगन आदेश पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार के आदेश
दिनांक 29.6.2016 की क्रियान्वति को स्थगित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक
9.2.2016 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 9.4.2020 को

.....(1).....

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहसीलदार खण्डार द्वारा दुकान की जाँच की जाकर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रेषित की जाने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 15.4.2020 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र को निलंबित किया जाकर दिनांक 15.4.2020 को ही प्रार्थी के विरुद्ध थाना खण्डार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी को बारबार हैरान व पेशान किया जाकर बार-बार प्रार्थी के विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज किये गये जिसके लिए प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.4.2020 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को पत्र प्रस्तुत कर जाँच किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक 304-312 दिनांक 15.4.2020 द्वारा निलंबित किया गया उक्त आदेश पर हस्ताक्षर दिनांक 5.5.2020 अंकित है। जबकि बाडमेर जिले के 24 राशन कार्डों पर फर्जी ट्रान्जेक्शन के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.4.2020 को जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को भिजवायी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में श्रीमति पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गयी जाँच में मुझ अपीलान्ट पर कोई गबन नहीं बताया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 2.7.2020 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर दिनांक 23.7.2020 को सुनवायी हेतु तलब किया गया किन्तु उस दिन प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा दिनांक 5.8.2020 को जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। इस प्रकार उक्त आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा यह अंकित नहीं किया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी कब व किस माध्यम से प्राप्त हुई है। यह तर्क भी दिया कि जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध अपनी पीओएस मशीन संख्या 11285 से 24 राशनकार्डों की फर्जी तरीके से राशन सामग्री का वितरण कर दिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 269 दिनांक 6.4.2020 से तहसीलदार खण्डार से करवायी जाने पर जिला बाडमेर के 24 राशनकार्डों पर फर्जी ट्रान्जेक्शन कर गेहूँ निकाला गया है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार को जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक/अभियोग/304-312 दिनांक 15.4.2020 उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर उक्त उचित मूल्य दुकान की अस्थायी वितरण व्यवस्था हेतु इसी ग्राम पंचायत के अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमदुर्गासिंह राठौड़ को अधिकृत किया गया तथा पीओएस मशीन एवं अवशेष स्टॉक का हस्तानान्तरण कराने हेतु तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन एवं राशन सामग्री का स्टॉक अटैचमेंट उचित मूल्य दुकानदार को नहीं सम्मलाया जाने एवं बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डों पर फर्जी ट्रान्जेक्शन कर 585 किलोग्राम गेहूँ के गबन करने के कारण उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0074 दिनांक 15.4.2020 दर्ज करवायी जाकर पत्र क्रमांक 371 दिनांक 20.4.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी हेतु दिनांक 8.5.2020 नियत की गयी किन्तु उचित मूल्य दुकान उक्त नियत दिनांक को सुनवायी हेतु उपस्थित नहीं होने पर पुन पत्रांक 452 दिनांक 18.6.2020, 533 दिनांक 2.7.2020 द्वारा उपस्थित होने हेतु लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया तथा अपीलान्ट ना तो कार्यालय में उपस्थित हुआ ओर ना कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी

प्राधिकार नत्र की शर्त संख्या 11,15,17(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार का प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/-रु समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्त एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुताबिक पैरोकार रसद श्री राजेश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डार की पीओएस मशीन संख्या 11285 से बाडमेंर जिले के 24 राशनकार्डों की राशन सामग्री का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाकर 585 किलोग्राम गेहूँ का गबन किये जाने का आरोप है। उक्त 24 राशनकार्डों की राशन सामग्री का फर्जी ट्रान्जेक्शन बाबत लगाये गये आरोप निराधार होने के संबंध में अपीलान्त डीलर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। अपीलान्त द्वारा उक्त संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष कथन किया है कि उसकी पीओएस मशीन संख्या 11285 हेक की जाकर उक्त 24 राशनकार्डों की राशन सामग्री का ट्रान्जेक्शन फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में उक्त पीओएस मशीन हेक होने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त कृत्य के लिए अपीलान्त के विरुद्ध थाना खण्डार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0074 दिनांक 15.4.2020 दर्ज होकर न्यायालय में जैरकार है जिसमें अपीलान्त पर लगाये गये आरोपों के संबंध में गहनता से जाँच होकर अपीलान्त पर लगाये गये आरोप निराधार है अथवा सही है के संबंध में पुष्टि की जानी है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार रहते हुए अपीलान्त के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने बाबत इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अगिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर